RAJYA SABHA

Friday, the 14th March, 2008/24 Phalguna, 1929 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Urea

221. SHRI TAPAN KUMAR SEN:††
SHRI PRASANTA CHATTERJEE:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the quantity of urea imported during 2004-05, 2005-06 and 2006-07;

(b) the estimated import during 2007-08;

(c) the cost of imported urea per tonne during the above years;

(d) the present cost of the imported urea; and

(e) the steps taken to reduce its import?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The quantity of urea imported on Government account during the year 2004-05 to 2006-07 & estimated imports during 2007-08 are as below:—

Year	Urea Imports (in lakh MT)		
	From Oman	From other sources	Total
2004-2005	0.00	6.41	6.41
2005-2006	13.25	7.31	20.56
2006-2007	18.37	28.82	47.19
2007-2008 (estimated)	19.06	50.57	69.63

(c) The weighted average Cost & Freight (C&F) price of the urea imports during the years 2004-05 to 2006-07 & provisional price for 2007-08 are as under:—

Year	Wt. Average C&F price (US $ per MT)	
	import from other sources	Import from OMAN
2004-2005	237.88	Nil
2005-2006	258.56	155.23
2006-2007	248.85	168.66
2007-2008 (provisional)	344.10	179.95

††The question was actually asked on the Floor of the House by Shri Tapan Kumar Sen.

(d) While the current international C&F prices are in the range of US$ 405-415 per MT, the prices are showing an increasing trend.

(e) There has been no investment in urea sector for the last 10 years. The major reasons are non availability of adequate natural gas for production of urea and the existing cost plus pricing regime for urea. Keeping in view the projected improvement in availability of gas from 2009 onwards, the Department is in the process of finalizing a new policy for investment in urea sector based on international benchmark in order to promote investment in urea sector and consequently to increase the indigenous production. Besides, Government is also committed to the revival of the closed fertilizer units.

MR. CHAIRMAN: Question No. 221. *(Interruptions).*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, ...*(Interruptions).*

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, today is the first anniversay of....*(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt the House. Please don't interrupt the House. *(Interruptions).* I would request the hon. Member to resume his place. *(Interruptions).* Question No. 221. *(Interruptions).* It is uncalled for disruption. Please resume your place. *(Interruptions).*

SHRI DINESH TRIVEDI: In respect of the people who were ....*(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: Mr. Trivedi, I request you to resume your place. *(Interruptions).* Please resume your place and allow the Question Hour to proceed. Question No. 221. *(Interruptions).* Please do not interrupt the House. *(Interruptions).* I am afraid the hon. Member is disturbing the proceedings.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, I stage a walkout.

[At this stage, the Hon. Member left the Chamber]

MR. CHAIRMAN: Question No. 221.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Mr. Chairman, Sir, a very serious situation is depicted by the hon. Minister's reply about our fertiliser consumption and fertiliser import. The agrarian crisis is deepening and dependence on urea import is increasing, reaching around 70 lakh tonnes in the current year, which is more than 35 per cent of the indgenous production of fertiliser. The import price is also continuously rising, now reaching 410 dollars per tonne, which is around Rs. 16,000 per tonne, compared to the domestic cost of production of Rs. 12,000 per tonne. In such a situation, my question to the hon. Minister is this. What is the share of the imported fertiliser in the total fertiliser subsidy bill of the Government? If it is a major part of the total subsdiy bill, how could the Government conceive of a policy of promoting investment in the urea sector based on international price parity benchmark, knowing the fact that import price is continuously increasing, now reaching a whopping 410 dollars per tonn? What is the logic of going into the international price parity policy?

श्री राम विलास पासवान: सर, यह बात सही है कि हमारा प्रोडक्शन कम है। अभी हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, वह यूरिया की कैपेसिटी 200 लाख टन है। अभी जो हमारी खपत है, वह इस साल में ढाई सौ लाख टन हो चुकी है। यदि हम देखें, तो पाएंगे कि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके अनुपात में हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता नहीं है। हमने 2005 में ओमान में ज्वाइंट वैंचर करके एक प्लांट लगाया था। उससे हमारे पास 18 मिलियन टन यूरिया आ रहा है। हमारा कुल प्रोडक्शन 218 मिलियन टन है। जो माननीय सदस्य का कहना है और उनकी बात सही भी है कि पिछले 15 सालों में फर्टिलाइजर सैक्टर में कोई इंवेस्टमेंट नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इंवेस्टर्स हैं-जो पॉलिसी हम

बनाते हैं, उस पॉलिसी में जो निवेशक हैं, फर्टिलाइजर उत्पादक हैं, उनको लगता है कि इसमें हमारा घाटे का सौदा है। उसके कारण यह होता है कि हम बाहर से होने वाले इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं। पिछले साल हमने 50 लाख टन यूरिया इम्पोर्ट किया, DAP इम्पोर्ट किया और MOP इम्पोर्ट किया। इस कारण इंटरनैशनल मार्किट में भी दाम बढ़ जाते हैं। अभी आपने मांग और उत्पादन के बारे में कहा है, तो यह अंतर दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमने दो काम किए हैं। एक तो यह देखना है कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं? दूसरा यह है कि जो बंद प्लान्ट्स हैं, जो 2003 में बंद हो गए थे, इसके लिए हम किसी पार्टी या सरकार को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि यूरिया बेस्ड थे। एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. के आठ प्लान्ट्स 2003 में बंद कर दिए गए थे। ये नेफ्था बेस्ड थे। नेफ्था बेस्ड में नेफ्था की कीमत काफी बढ़ी हुई है और गैस में हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमें कुल मिलाकर 41 MMS CMD चाहिए, जो अभी 29 MMS CMD है। यह खुशी की बात है कि यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि जो बंद प्लान्ट्स हैं, एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. के आठ बंद प्लान्ट्स हैं, इनमें गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर, रामागुन्डम, हल्दिया, दुर्गापुर ये सभी जो बंद प्लान्ट्स हैं, इनको दोबारा चलाने का निर्णय लिया है। इनमें कुल मिलाकर 8 मिलियन टन, अस्सी लाख टन का उत्पादन होगा। इसके लिए हमें गैस चाहिए। जी.ओ.एम. (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) की बैठक हुई थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यह तय हुआ है कि जो फर्टिलाइजर्स प्लान्ट्स हैं, उन्हें प्रायोरिटी के आधार पर गैस का आवंटन किया जाएगा। जितनी जल्दी गैस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ये सभी प्लान्ट्स चालू कर दिए जाएंगे। दूसरा मुद्दा एम.आर.पी. का मुद्दा है।

MR. CHAIRMAN: Can we have a short reply.

श्री राम विलास पासवान: सर, हम इसलिए बता रहे हैं, जिससे ज्यादा सप्लीमेंट्री पूछने का मौका नहीं मिले।

श्री सभापति: वे तो पूछें जाएंगे।

श्री राम विलास पासवान: जहां तक पैरिटी का सवाल है, हम चाहते हैं, हमने जो पॉलिसी बनाई है, इस प्रपोज्ड पॉलिसी में जो इम्पोर्टेन्ट प्राइसेज़ हैं, उसकी पैरिटी के आधार पर हम सोच रहे हैं कि निवेशक को मिले। लास्ट में कहना चाहता हूं कि इन्होंने तीन प्रश्न उठा दिए हैं। एक तो सब्सिडी का मामला है, एक प्रॉडक्शन और तीसरा पैरिटी का मामला उठाया है। जहां तक सब्सिडी का सवाल है, हमारे पास सब्सिडी का आंकड़ा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सब्सिडी लगातार बढ़ रही है। पिछली बार 45,000 करोड़ रुपए दी थी, उससे पहले 25,000 करोड़ रुपए दी थी, इस बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार जी की रिपोर्ट के मुताबिक जाएं तो 75,000 करोड़ रुपए है। यह सब्सिडी 75,000 करोड़ रुपए है। हम इसमें किसान पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते हैं। हमारे यूरिया का प्राइस 4,830 रुपए एम.आर.पी. है ...(**व्यवधान**)... सर, मैं खत्म कर रहा हूं। हमारा जो यूरिया है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: डा. साहब।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जो सदस्यों के लिए लागू होता है, वह मंत्रियों के लिए क्यों नहीं लागू होता है?

श्री राम विलास पासवान: सर, जब हम अपोजीशन में थे तो कहते थे मंत्री...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप जवाब दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: हम जवाब दे रहे हैं। यूरिया हम 15,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदते हैं और किसान को 4,830 रुपए में देते हैं, बाकी सब्सिडी में देना पड़ता है। डी.ए.पी. 25,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदते हैं और किसान को 9,300 रुपए में देते हैं। एम.ओ.पी. 12,000 प्रति टन खरीदते हैं, किसान को 4000 रुपए प्रति टन देते हैं। इस कारण से सब्सिडी बढ़ रही है। ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: एक नियम बनाइए 'to prevent atrocities by Ministers against Members of the House'.

MR. CHAIRMAN: Thank you for the suggestion.

श्री राम विलास पासवान: आपको खुशी होनी चाहिए कि सरकार ने कोई दाम नहीं बढ़ाया है, किसान पर कोई बोझ नहीं डाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्राडक्शन बढ़े, निवेश भी हो और इसके लिए सरकार नीति बना रही है। इसके बाद सप्लीमेंट्री का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री तपन कुमार सेन: कप्लीमेंट्री का प्रश्न है। I would like to thank the hon. Minister for the detailed answer. But this substantiates that their banking on the import parity price for the future investment policy will further increase the burden on the Government. And that is a wrong economic logic. The Ministry may kindly review it. And, scondly, he has said that there is no investment in the urea sector in the last 10 years. It is also a fact, which you have not said, that the indigenous urea production capacities in the country had been killed by the successive Governments. At that time, it was argued that the cost of imported fertiliser was much cheaper than the cost of domestic production and hence there was nothing wrong in importing it. Now, we have landed in a situation where we have to import more than 35 per cent of our indigenous production; all the agrarian inputs have been increasing, and that is increasing the burden of the Government...

MR CHAIRMAN: Supplementary, please.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I am coming to the supplementary. I am grateful that the Government has decided to revive all the eight fertiliser plants which we are having. But you must also consider the existing units which have not yet been closed down...

MR. CHAIRMAN: Supplementary, please.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I am putting the supplementary. I want to know whether the plants which have not yet been closed, like the Madras Fertilisers FACT are also being pushed towards closure. I want to know whether you are going to protect them...

MR. CHAIRMAN: Question please.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: That is number one. And, what is the roadmap for reviving the public sector plants with gas because, till now, out of the total gas production, only 25 per cent is given to the fertiliser sector?

MR. CHAIRMAN: Thank you. Is that the question?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: You have said that you require around 41 mmscfd.

MR. CHAIRMAN: I am afraid...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I am just completing, Sir. What is the roadmap for making gas available for reviving the fertiliser sector? This is a very important question because it is related to a very important sector of the economy which takes care of 52 per cent of country's population, and the whole of our agrarian economy. I have completed, Sir.

MR. CHAIRMAN: I am afraid this is happening from both the sides. But if there are long questions and longer answers, then the Chair will have to rule both out of order. I think questions should be questions and answers should be short, crisp and to the point. *(Interruptions)* No, you have finished your point. आप बैठ जाइए प्लीज़।

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने पहले ही कह दिया कि हमारा Import बढ़ रहा है, मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी सब्सिडी बढ़ रही है। हमने पहले ही कह दिया कि यदि हम सब्सिडी घटाते हैं, तो किसान के ऊपर भार पड़ेगा, जो भार हम किसान के ऊपर नहीं डालना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ा दी जाए, तो सरकार की यह मंशा नहीं है। हम फर्टिलाइजर की कीमत नहीं बढ़ाना चाहते हैं। भले ही सरकार को सब्सिडी के रूप में ज्यादा देना पड़े, सब्सिडी तो ज्यादा बढ़ ही रही है, इसके लिए हम चाहते हैं कि अभी जो हमारा प्लांट है, वह 70 परसेंट प्लांट गैस के ऊपर है और 30 परसेंट प्लांट फ्यूल के ऊपर और नाफ्था के ऊपर है, लेकिन 30 परसेंट की सब्सिडी 70 परसेंट लगती है और 70 परसेंट की सब्सिडी 30 परसेंट लगती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह गैस के ऊपर हो जाए।

गैस के सम्बन्ध में मैंने कह दिया कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि हम priority basis पर देंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2009 तक गैस की availability हो जाएगी।

जहां तक बन्द प्लांट, FACT का सवाल है, मैंने इस सदन में कहा था कि हम FACT और MFL को बन्द नहीं होने देंगे। FACT में revival के लिए 200 करोड़ रुपया दिया गया है। जब तक गैस available नहीं होगी, FACT बन्द नहीं होगा। हम MFL के लिए भी कैबिनेट में जा रहे हैं। उसके भी बन्द होने का सवाल नहीं उठता है। हमारी सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी प्लांट बन्द नहीं होगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, बहुत छोटा सवाल है कि क्या सरकार ने इस फर्टिलाइजर की मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी से बचने के लिए राज्य सरकारों को सीधा फर्टिलाइजर आयात करने का कोई निर्देश दिया है? अगर यह निर्देश दिया है, तो उसका दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस आधार पर negotiate होगा, इसके भी कोई directions दिए हैं और क्या ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम और अधिक नहीं बढ़ेंगे? अगर रासायनिक खाद की इतनी दिक्कत है और बहुत समय तक दिक्कत है और उसके दाम बढ़ने से किसानों को आत्महत्या करने पर भी मजबूर होना पड़ता है, तो क्या सरकार जैविक खाद का अधिक-से-अधिक उपयोग करने की कोई नीति अपनाएगी और धीरे-धीरे imported और यहां के इस रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद, जिसका भंडार भारत में है, उसका उपयोग करने की कोई नीति अपनाएगी?

श्री राम विलास पासवान: सर, जहां तक यह सवाल है, यह खाद कम-controlled है। इसमें सिर्फ यूरिया 50 परसेंट control में है, बाकी सब de-control में है। दुर्भाग्य से यह है तो de-control में, लेकिन हर चीज के लिए जवाब मंत्री को देना पड़ता है। De-control का मतलब है कि जैसे आप पैसा देकर लोटा-गिलास खरीदते हैं, उसी तरह से आप जाइए और कम्पनी से खरीदिए। जो सब्सिडी का पैसा है, उसको सरकार देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Monitoring हमको करनी पड़ती है। DAP की कमी हो रही है, तो यहां हाउस में हल्ला होता है, खाद की कमी होती है, तो हल्ला होता है। सिर्फ 50 परसेंट यूरिया का movement हमारे control में है, बाकी 50 परसेंट यूरिया de-control में है, MOP de-control में है, DAP de-control में है। लोग खरीदते हैं, सरकार हो या जो भी लोग हों, कम्पनी से खरीदते हैं। पहले तो यह स्टेट में पहुंचता था, तब हम सब्सिडी देते थे। तब हमने कहा कि जब यह डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पहुंचेगा, तब सब्सिडी देंगे। हमने वेबसाइट बना दी है और अब हमने कह दिया है कि नहीं, जब ब्लॉक लैवल पहुंचेगा, तब हम सब्सिडी देंगे। इस तरह हम इन सारी चीज़ों को स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं।

उसी तरीके से जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, अगर आप यूरिया का प्राइस, डीएपी और एमओपी का प्राइस रोज़ देखेंगे, तो जैसा इन्होंने कहा है, तीन गुना या चार गुना बढ़ रही है। हर महीने व हर दिन प्राइस बढ़ रही है। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, वे डर रहे हैं कि कैसे हम इम्पोर्ट करें, चूंकि हमको जो पैसा मिलता है, वह एवरेज मिलता है, लेकिन प्राइस यहां रोज़ बढ़ रही है। इसलिए पिछली बार राज्य सरकार ने, प्राइवेट सेक्टर वालों ने कह दिया कि हम यह नहीं मंगाएंगे। जहां उन्हें 12 लाख टन मंगाना था, वहीं उन्होंने कहा कि केवल तीन लाख टन ही मंगाएंगे।

ऐसे में हम लोगों ने कहा कि हम इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के द्वारा मंगाएंगे, लेकिन आईपीएल के पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। इसलिए राज्य सरकार को पहले ही कह दिया गया और मीटिंग में राज्य सरकार ने इसके लिए एग्री भी किया कि आप हमको यूरिया दीजिए और हम डिस्ट्रिब्यूशन करवा देंगे। इस तरह राज्य सरकार को कोई कॉंट्रैक्ट नहीं करना था, कॉंट्रैक्ट आईपीएल के द्वारा हुआ। राज्य सरकार को केवल डिस्ट्रिब्यूशन करवाना था और हमें खुशी है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने उसका डिस्ट्रिब्यूशन करवाया।

जहां तक जैविक खाद का सवाल है, अभी तक केवल रासायनिक खाद या कैमिकल फर्टिलाइज़र, जिसमें यूरिया, पोटाश और डीएपी, ये तीन चीज़ें आती हैं, इन तीनों खादों के ऊपर सब्सिडी मिलती है। हमने घोषित कर दिया है कि हम जो नई पॉलिसी बना रहे हैं, उसको हम nutrient base के ऊपर कर रहे हैं। जो पौष्टिक तत्व है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि उसमें सारे के सारे जो भी सल्फर हैं, चाहे जैविक खाद हों, कम्पोस्ट हो या अन्य हो, ये उसमें कवर हो जाएंगे। इस तरह हमारा nutrient base सब्सिडी का प्लान हैं हो सकता है कि उसमें सरकार को थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़े, लेकिन इससे किसान को बहुत फायदा होगा।

MR. CHAIRMAN: Dr. Farooq Abdullah.

DR. FAROOQ ABDULLAH:Sir, my question has been answered.

श्री बनवारी लाल कंछल: सर, जब हमारे देश में खाद की कमी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो साग-सब्जी बेचने के लिए कॉर्पोरेट घरानों को आप लगा रहे हैं, क्या उनके द्वारा आप खाद के कारखानों को लगाने के लिए भी कोई योजना बनाएंगे? जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों में होता है कि यह माल लोगे तो इसके साथ यह भी लेना पड़ेगा, उसी तरह क्या इन कॉर्पोरेट घरानों को भी आप कहेंगे कि अगर आप शॉपिंग मॉल खोलेंगे तो आपको खाद की फैक्ट्री भी खोलनी होगी? क्या आप कोई ऐसी योजना बनाएंगे?

श्री राम विलास पासवान: इन्होंने एक नया सुझाव रखा है, उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।

कृषि के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच तालमेल

*222. **श्री रूद्रनारायण पाणि:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनका मंत्रालय राज्यों के कृषि विभागों के साथ किस प्रकार तालमेल रखता है;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों का कोई सम्मेलन बुलाया गया था;

(ग) देश में किसानों के वास्तविक कल्याण के लिए अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई होगी;

(घ) क्या कृषि बजट को लेकर राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच अब तक कभी कोई टकराव की स्थिति पैदा हुई है; और

(ङ) क्या सरकार 'कृषि बजट' को 'रेल बजट' की तरह तैयार किए जाने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) चूंकि कृषि राज्य का विषय है इसलिए कृषि के विकास हेतु नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है और भारत सरकार उचित वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन के जरिए राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण करती है। कृषि मंत्रालय विशेषकर राज्यों की बैठकों और सम्मेलनों यथा-खरीफ/रबी सम्मेलन के जरिए राज्यों के कृषि विभागों के साथ समन्वय करता है ताकि कृषि के विकास, अपेक्षित परामर्श के बाद राज्यों की वार्षिक कार्ययोजनाओं के अनुमोदन और मानेटरिंग की प्रक्रिया के जरिए मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों पर उनकी राय, सुझाव और फीड बैक प्राप्त किए जा सकें। राज्य सरकारों से भी महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों पर परामर्श लिया जाता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय दिनांक 23.12.2006 को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में राज्यों से परामर्श लिया गया।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय के तहत तीन विभागों का योजना परिव्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	विभाग	2005-06	2006-07	2007-08
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	4179	4800	5520
2.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	669	777	910
3.	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1150	1350	1620